# कैनडा ने अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया

## कैनडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर अफसोस जताया

■ **कैनडा के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कैनडा में भारत की कार्रवाई को अनुचित, तनाव बढ़ाने वाली और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है। कैनडा ने यह भी कहा है कि, प्रतिशोध में वह कोई भी एकतरफा कार्रवाई नहीं करेगा।**

ओटावा, 20 अक्टूबर (वार्ता)। कनाडा ने भारत में तैनात अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है और दोनों देशों के बीच खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या को लेकर बनी स्थिति पर अफसोस जताते हुए यह भी कहा है कि भारत का निर्णय कनाडा का ध्यान हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की वैध जांच से नहीं भटकाएगा।

कनाडा के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार देर रात एक बयान जारी करके यह जानकारी दी। बयान में कनाडा ने भारत की कार्रवाई को अनुचित, तनाव बढ़ाने वाली और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है। कनाडा ने यह भी कहा है कि वह प्रतिशोध में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

बयान में कहा गया, ''कनाडा ने पुष्टि की है कि भारत ने 20 अक्टूबर तक नयी दिल्ली में 21 कनाडाई राजनयिकों और उनके आश्रितों को छोड़कर सभी के लिए एकतरफा प्रतिरक्षा हटाने की अपनी योजना को औपचारिक रूप से सूचित किया था। इसका मतलब है कि 41 कनाडाई राजनयिकों और उनके 42 आश्रितों की प्रतिरक्षा छीन लिए जाने का खतरा था।

बयान में कहा गया, इन कनाडाई राजनयिकों और उनके परिवारों पर भारत की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप सुरक्षा निहितार्थ को देखते हुए, कनाडा ने भारत से उनके सुरक्षित प्रस्थान की सुविधा प्रदान करने की मांग की है।

बयान में कहा गया, राजनयिक विशेषाधिकारों को एकतरफा ढंग से हटाना राजनयिक संबंधों पर वियना संधि सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत है।भारत द्वारा की गई यह कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित और तनाव बढ़ाने वाली है।

कनाडा ने कहा, ''भारत ने उन सभी कनाडाई राजनयिकों को मान्यता दी थी जिन्हें वे अब निष्कासित कर रहे हैं। वे सभी राजनयिक सद्भावना से और दोनों देशों के व्यापक लाभ के लिए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे।''

बयान में कहा गया, राजनयिक छूट का सम्मान किया जाना चाहिए और मेजबान देश द्वारा इसे एकतरफा रद्द नहीं किया जा सकता है। यदि हम इस मानदंड को तोड़ने की अनुमति देते हैं, तो कहीं भी कोई भी राजनयिक सुरक्षित नहीं रहेगा। इस प्रकार, कनाडा सरकार राजनयिक मानदंडों का सम्मान करना जारी रखेगी और इस कार्रवाई का प्रतिकार नहीं करेगी।''

कनाडा के विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत का निर्णय निज्जर की हत्या की कनाडा की वैध जांच से ध्यान नहीं भटकाएगा। इस मामले में कनाडा की प्राथमिकताएं सत्य का पता लगाना, कनाडाई लोगों की सुरक्षा और हमारी संप्रभुता की रक्षा बनी हुई हैं।''

बयान में कहा गया, कनाडा अंतरराष्ट्रीय कानून का बचाव करना जारी रखेगा, जो सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होता है। कनाडा भारत के साथ जुड़ना जारी रखेगा और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे बातचीत के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

कनाडा ने कहा, दुर्भाग्य से, इस सामूहिक निष्कासन से हमारे परिचालन पर असर पड़ेगा और ग्राहक सेवा प्रभावित होगी।अब हम अगली सूचना तक वाणिज्य दूतावासों में सभी व्यक्तिगत सेवाओं को अस्थायी रूप से रोकने के लिए मजबूर होंगे।

## भारत ने कैनडा के बयान का विरोध जताया

नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर (वार्ता)। भारत ने कनाडा के 41 राजनयिकों को कम किए जाने के फैसले को कनाडा सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन बताए जाने की आलोचना की है और कनाडा के बयान को खारिज कर दिया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शुक्रवार को यहां एक बयान में कहा, हमने भारत में कनाडाई

■ **भारत ने कैनडा के 41 राजनयिकों अपने देश से हटाकर वापस भेजे जाने के फैसले को कैनडा सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन बताए जाने की आलोचना की है और कैनडा के बयान को खारिज कर दिया है।**

राजनयिक उपस्थिति के संबंध में 19 अक्टूबर को कनाडा सरकार का बयान देखा है। हमारे द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति, भारत में कनाडाई राजनयिकों की बहुत अधिक संख्या और हमारे आंतरिक मामलों में उनका निरंतर हस्तक्षेप, नयी दिल्ली और ओटावा में दोनों देशों के राजनयिकों की उपस्थिति में समानता की मांग का आधार बना।

# न्यूज़क्लिक के प्रमुख को राहत देने से कोर्ट ने फिलहाल इन्कार किया

## कोर्ट ने न्यूज़क्लिक मामले में प्रबीर पुरकायस्थ और पोर्टल के एच.आर. हैड अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को पांच दिन के लिए बढ़ा दी

■ **दिल्ली पुलिस ने जमानत का इस आधार पर विरोध किया कि, भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने और देश में असंतोष पैदा करने के लिए प्रबीर पुरकायस्थ के समाचार पोर्टल को चीन से बड़ी राशि मिली थी।**

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और वेबसाइट के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने न्यूजक्लिक मामले में प्रबीर पुरकायस्थ और वेबसाइट के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को पांच दिन के लिए बढ़ा दी। दोनों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि चीन के पक्ष में प्रचार करने के लिए समाचार पोर्टल को विदेश से पैसे मिले थे। दिल्ली पुलिस ने न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया और उनकी हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया जिसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने यह आदेश पारित किया। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने तीन अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने और देश में असंतोष पैदा करने के लिए समाचार पोर्टल को चीन से बड़ी राशि मिली थी। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए पुरकायस्थ ने पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म (पीएडीएस) समूह के साथ मिलकर साजिश रची थी।

पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी में नामजद और डेटा के विश्लेषण में सामने आए संदिग्धों पर तीन अक्टूबर को दिल्ली में 88 और अन्य राज्यों में सात स्थानों पर छापे मारे गए थे। न्यूजक्लिक के कार्यालयों और पत्रकारों के आवासों से लगभग 300 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। छापेमारी के बाद विशेष प्रकोष्ठ ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में नौ महिला पत्रकारों समेत 46 लोगों से पूछताछ की थी।

# 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारी भी वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार

■ **राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक जुलाई को होने वाली सालाना वेतन वृद्धि दी जाए**

■ **हाईकोर्ट ने छैल बिहारी शर्मा व डेढ़ दर्जन अन्य लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया।**

जयपुर, 20 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि, तीस जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक जुलाई को होने वाली सालाना वेतन वृद्धि अदा किया जाए। जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता छैल बिहारी शर्मा व डेढ दर्जन अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि, राज्य सरकार ने रिवाइज़ वेतन स्केल नियम, 2008 व 2017 के जरिए प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि में एकरूपता लाने के लिए सालाना वेतन वृद्धि की तारीख एक जुलाई तय कर की है। इसके चलते जो कर्मचारी एक दिन पहले यानी तीस जून को रिटायर हो जाते है, उन्हें एक वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित रहना पड़ता है। कर्मचारियों की पेंशन और अन्य परिलाभों पर भीइसका नकारात्मक असर पड़ता है। याचिका में कहा गया कि, सरकार कर्मचारी को वेतन वृद्धि पूर्व में काम कर चुकने वाली अवधि के आधार पर देती है ना कि अग्रिम अवधि के लिए। ऐसे में कर्मचारी एक साल काम करने के बाद तीस जून को रिटायर होते हैं। ऐसे में उन्हें भी एक जुलाई को लगने वाली सालाना वेतन वृद्धि लेने का अधिकार है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट भी तय कर चुका है कि, जिस कर्मचारी ने रिटायर होने से पूर्व एक साल तक काम किया है, उसे उस साल की वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। याचिका में बताया गया कि, याचिकाकर्ता तीस जून, 2016 को रिटायर हुए थे, लेकिन राज्य सरकार उन्हें एक जुलाई को दी जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दे रही है।

राज्य सरकार की ओर से अपने जवाब में कहा गया कि, उनकी ओर से रिवाइज़ वेतन स्केल नियम के तहत कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने तीस जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी एक जुलाई को दी जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि देने के आदेश दिए हैं।

## इज़राइल ने ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

प्रमाण मिले हैं कि वह शत्रु की मदद कर रहा है और अरबी में और अंग्रेजी भाषा में हमास का प्रचार कर रहा है।

बयान में कराई ने कहा कि इजराइल ''युद्ध'' की स्थिति में है और हम ऐसी खबरों के प्रसारण की अनुमति नहीं देंगे जो हमारे लिए खतरा हों।''

## 'सरकार के प्रचार कार्यों में सेना को लगाना अनुचित है'

नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर (वार्ता)। कांग्रेस नेता कर्नल (अवकाश प्राप्त) रोहित चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार अपनी उपलब्धियों के प्रचार के लिए सेल्फी प्वाइंट बनाने में सेना के जवानों का इस्तेमाल कर रही है जो अनुचित और पूरी तरह से गलत है।

कर्नल चौधरी ने आज यहां कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सेना का

■ **कांग्रेस नेता एवं कर्नल (अवकाश प्राप्त) रोहित चौधरी ने कहा कि प्र.मंत्री मोदी ने सरकारी योजनाओं के प्रचार के पोस्टर सेना को थमा दिये हैं।**

काम देश की सेवा करना है और किसी भी सरकार को अपनी उपलब्धियों के प्रचार के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, ''मोदी सरकार ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए सेना के हाथ सरकारी योजनाओं के पोस्टर थमा दिए हैं।

डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक सर्कुलर जारी किया है कि देश में मोदी सरकार की योजनाओं से जुड़े 822 सेल्फी पॉइंट्स बनेंगे।

# किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद

■ **पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण करने व कई दिन तक दुष्कर्म करने वाले राहुल हुसैन पर सजा के साथ एक लाख रु. का जुर्माना भी लगाया।**

■ **कोर्ट ने कहा कि नाबालिग की सहमति मान्य नहीं है और आरोपी के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती।**

जयपुर, 20 अक्टूबर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3, महानगर प्रथम, ने 14 साल की बालिका का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राहुल हुसैन को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 19 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख अस्सी हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि, अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। यदि इसमें पीड़िता की सहमति भी होती तो भी वह दुष्कर्म के अपराध की श्रेणी में ही माना जाता, क्योंकि नाबालिग पीड़िता की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है। अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर न केवल उसे शारीरिक कष्ट दिया,बल्कि उसे भावनात्मक रूप से भी चोट पहुंचाई है। ऐसे में अभियुक्त के कृत्य को ध्यान में रखते हुए उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि इस संबंध में पीड़िता के पिता ने 22 मई, 2022 को मुहाना थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि 21 मई की शाम 6 बजे से बेटी गायब है।

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 27 दिसंबर को गाज़ियाबाद से अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त ने पीड़िता को दिल्ली और नोएडा ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया था। इस पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप पत्र पेश किया।

अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि, प्रकरण में उसे फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाते हुए जुर्माने से दंडित किया है।

## 'प्रधानमंत्री ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

तथा ''अन्नपूर्णा फूड पैकेट'' योजना के तहत खाना पकाने के तेल और नमक जैसे कांग्रेस के कई वादे और हैं।'' उन्होंने कहा कि ये सभी लाभ भाजपा को परेशान कर रहे हैं।

प्रियंका ने कहा कि उनकी रैली में आए भारी जनसमूह से संकेत मिलता है कि कांग्रेस सरकार की योजनाओं ने इन लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है और कांग्रेस राज्य में सत्ता में वापसी करेगी।

## केन्द्रीय चुनाव ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

मौजूद थे। बैठक में भाजपा की दूसरी सूची को लेकर मंथन करके नामो पर अंतिम मुहर लगाई गई। कहा जा रहा है कि दूसरी लिस्ट अब कभी भी आ सकती है। लिस्ट में 50 से 70 नाम के बीच घोषणा होने की संभावना है। दूसरी लिस्ट में भी भाजपा नए चेहरों को मौका दे सकती है। दो या तीन सांसद विधानसभा चुनाव मैदान में उतारे जा सकते हैं। वहीं, लिस्ट में मौजूद विधायकों में से करीब 45-50 विधायकों को फिर से विधानसभा चुनाव का टिकट मिल सकता है। बताया जा रहा है कि, 8 से 10 सीटों पर भाजपा नए प्रत्याशियों को टिकट देकर चुनाव में उतारेगी।

बैठक में, पहली सूची के बाद प्रदेश में हुए चौतरफा विरोध को कम करने की रणनीति भी बनाई गई। बताया जा रहा है कि, दूसरी सूची के बाद जो विरोध होगा उसे कोर ग्रुप के सभी नेता डैमेज कंट्रोल करके शांत करेंगे। चर्चा है कि, इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रदेश के कोर ग्रुप को देने दी है।

गौरतलब है कि, दूसरी लिस्ट पर सर्वसम्मति बनाने के लिए पिछले तीन दिनों में दो बार भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है। 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। वहीं, गुरुवार को केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रह्लाद जोशी के आवास पर एक बार फिर कोर ग्रुप की बैठक हुई।

# सोनिया और राहुल सहित 40 नेता छत्तीसगढ़ में स्टार प्रचारक होंगे

■ **कांग्रेस की ओर से घोषित स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकाजुर्न खड़गे, मु.मंत्री भूपेश बघेल के साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा, अधीर रंजन चौधरी, अजय माकन और कुमारी शैलजा प्रमुख हैं।**

नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर (वार्ता)। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की।

कांग्रेस की ओर से घोषित स्टार प्रचारकों में खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बघेल के साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा, अधीररंजन चौधरी, अजय माकन और कुमारी शैलजा प्रमुख हैं।

इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया, पंजाब के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, दीपक बैज, राजीव शुक्ला, दीपक बैज, टीएस सिंहदेव , फूलो देवी नेताम, मोहन मरकाम, के राजू, अलका लांबा, रंजीत रंजन, पीएल पुनिया, भक्त चरण दास, शरत पटनायक, सप्तगिरी शंकर उलाका, डॉ. चंदन यादव, विजय जांगिड़, रजनीश तिवारी, कैप्टन अजय सिंह यादव, शिवाजी राव मोघे, इमरान प्रतापगढ़ी, राजेश लिलोथिया, शिव कुमार डहरिया, रवीन्द्र चौबे, अमरजीत भगत, प्रेमसाय सिंह टेकाम, नंदकुमार साय, शफी अहमद, नेटा डिसूजा, श्रीनिवास बी वी और प्रदीप जैन आदित्य शामिल हैं।

# माकन ने गहलोत से कहा, पुरानी ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

राजनीति का ज्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए वह घबरा गए और अशोक गहलोत को हैण्डिल नहीं कर सके। सी.ई.सी. के समक्ष आए कई सिंगल नामों पर पुनः विचार किया जा रहा है और अब वैकल्पिक नाम तलाशने की जिम्मेदारी माकन और वासनिक पर होगी।

पार्टी के अन्दरुनी सूत्र बताते हैं कि गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में अपने पक्ष के उम्मीदवारों को एकजुट करने की कोशिश में हैं, लेकिन पासा बिल्कुल ही पलट गया लगता है।

सूत्र बताते हैं कि तीनों नेताओं ने कल रात एक लम्बी मीटिंग की। मीटिंग आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी और गहलोत यदि दिल्ली में मौजूद नहीं रहते हैं तो उनसे फोन पर चर्चा की जाएगी।

बताया जाता है कि अजय माकन ने गहलोत से कहा है कि वह पुरानी बातें भूलकर आगे बैठें और कांग्रेस के हित में कार्य करें ताकि पार्टी राजस्थान में पुनः सत्ता में आ सके।

दिलचस्प यह है कि अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी कल शाम मुलाकात की।

सूत्रों ने बताया कि खड़गे या उनकी बात सुनने वाले अन्य किसी को भी गहलोत यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि निवर्तमान विधायकों को फिर से टिकट क्यों दिया जाना चाहिए। उन्होंने इसके चार कारण बताए हैं:-

1-जिन विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, वे निर्दलीय प्रत्याशी के रुप में चुनाव लड़कर कांग्रेस प्रत्याशियों को ही हराएंगे।

2- वे यह आरोप लगाएंगे कि उनके निर्दलीय रुप से चुनाव लड़ने के लिए मैं (अशोक गहलोत) जिम्मेदार हूँ।

3- कल को जब हमें सरकार के गठन के लिए और विधायकों की जरुरत होगी, तब वे हम पर विश्वास नहीं करेंगे और आरोप लगाएंगे कि हम निहित स्वार्थों के लिए ही उन्हें साथ रखते हैं।

4- ऐसी सीटों पर ही टिकट काटें, जहां पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे किसी निवर्तमान विधायक को हराने की स्थिति में हो।

अशोक गहलोत ने अपने तर्क और समझ को खड़गे के समक्ष स्पष्ट किया क्योंकि लगता है कि खड़गे ही गहलोत की बात सुन रहे हैं और उधर गहलोत उन निवर्तमान विधायकों के टिकट बरकरार रखने की बड़ी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से अधिकांश के खिलाफ भारी सत्ता विरोधी लहर है।

## आंशिक...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

सितम्बर 2025 को दिखेगा जो कि पूर्ण चन्द्रग्रहण होगा। इससे पहले 8 नवम्बर 2022 को पूर्ण चन्द्रग्रहण हुआ था।

## 'शिकायत वापस ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

तीन पृष्ठ लंबे शपथ पत्र में दावा किया कि मोइत्रा के उनके साथ संसद में लॉग इन करने का पासवर्ड साझ किया था, ताकि दर्शन सीधे मोइत्रा की ओर से प्रश्न पोस्ट कर सके।

उन्होंने दावा किया कि मोइत्रा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शर्मिंदा करने के लिए गौतम अडानी को निशाना बनाया।

मोइत्रा ने शपथ पत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाया कि न तो यह अधिकारिक लैटरहैड पर है और न इसे नोटरी से प्रमाणित करवाया गया है।

महुआ ने एक बयान में कहा शपथ पत्र सफेद कागज पर है, न कि लेटर हैड पर और न ही यह नोटरी से प्रमाणित है देश का एक अति प्रतिष्ठित और शिक्षित व्यापारी ऐसा क्यों करेगा जब तक के इसके लिए उसके सिर पर बंदूक न रखी गई हो।

उन्होंने आरोप लगाया इस पत्र की सामग्री एक मजाक है। इसका प्रारूप निश्चित रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय के किसी मूर्ख ने बनाया होगा जो भाजपा की आईटी सेल में रचनात्मक लेखक भी है, इसने मोदी और अडानी का स्तूती शास्त्र है जबकि उनके दृढ़ विरोधी का संपर्क मुझसे और मेरे कथित भ्रष्टाचार से जोडा जा रहा है।

लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने दुबे और देहराई से कहा है कि वे मोइत्रा के खिलाफ अपने आरोपों के संबंध में उसके समक्ष बयान दें। लोअसभा अध्यक्ष ने कमेटी को महुआ के विरूद्ध आरोपों की जांच के आदेश दिए है जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते है और इन पर महुआ को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

## बिजनेसमैन हीरानंदानी महुआ मोइत्रा के राज उजागर करेंगे

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। टी.एम.सी. सांसद महुआ मोइत्रा पर कैश और गिफ्ट लेकर सवाल पूछने के आरोप लग रहे हैं। इस मामले में आरोप लगे हैं कि उन्होंने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली थी। अब खुद हीरानंदानी ने एफिडेविट के जरिए कुछ दावे किए हैं और सरकारी गवाह बन गए हैं। एफिडेविट में दर्शन हीरानंदानी ने दावा किया है कि उनकी पहली मुलाकात महुआ मोइत्रा से तब हुई थी, जब वह विधायक थीं। 2017 में हुई बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में वह गए थे, उसी दौरान महुआ मोइत्रा उनके संपर्क में आई थीं। दोनों ने एक-दूसरे के नंबर शेयर किए और बातें भी होने लगीं। दर्शन हीरानंदानी ने कहा कि जब वह सांसद बन गईं तो बातें और ज्यादा हुईं। यही नहीं महुआ मोइत्रा काफी महत्वाकांक्षी हैं और वह अकसर उनसे कुछ डिमांड रखा करती थीं।

# रूस ने भारत से क्रूड ऑयल का पेमैंट चीन की मुद्रा में करने की मांग की

## भारत ने रूस की इस मांग को सिरे से खरिज किया और पैट्रोलियम कंपनियों को भी इस तरह का एक भी भुगतान नहीं करने का आदेश जारी किया

■ **गौरतलब है कि, देश की सबसे बड़ी सरकारी रिफाइनरी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पिछले दिनों रूसी क्रूड ऑयल के लिए युआन (चीन की मुद्रा) में भुगतान किया था। हालांकि, सरकार ने तभी से इस पर रोक लगा दी है।**

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। पिछले कुछ समय से चीन और रूस लगातार करीब आ रहे हैं। पिछले महीने जी20 समिट के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत का दौरा नहीं किया, लेकिन इसके बाद भी वह चीन पहुंचे, जिसपर पूरी दुनिया की निगाहें टिक गईं। रूस और चीन की दोस्ती धीरे-धीरे मजबूत हो रही है, जो न सिर्फ पश्चिमी देशों के लिए, बल्कि भारत के लिए भी चिंता का सबब है। इस बीच, भारत को क्रूड ऑयल बेच रहा रूस चीनी मुद्रा में पेमैंट की मांग कर रहा है। हालांकि, मोदी सरकार ने कच्चे तेल के इम्पोर्ट के लिए चीनी मुद्रा में भुगतान करने के रूसी तेल सप्लायर्स के दबाव को खारिज करके झटका दे दिया। इसके पीछे बीजिंग और नई दिल्ली के बीच लंबे समय से जारी तनाव वजह है।

बातचीत में सीधे शामिल एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी और सरकार के स्वामित्व वाली तेल रिफाइनरी के एक अन्य वरिष्ठ व्यक्ति के अनुसार, कुछ रूसी तेल सप्लायर्स युआन में भुगतान की मांग कर रहे हैं। दोनों लोगों ने पहचान उजागर न करने को कहा क्योंकि चर्चाएं निजी हैं। इन दो लोगों और दो अन्य भारतीय सरकारी अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उन अनुरोधों पर सहमत नहीं होगी। भारत की लगभग 70 फीसदी रिफाइनरी सरकारी स्वामित्व वाले हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें वित्त मंत्रालय के निर्देशों का पालन करना होगा।

सबसे बड़ी सरकारी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पिछले दिनों रूसी कच्चे तेल के लिए युआन का भुगतान किया था। हालांकि, सरकार ने तब से उस पर रोक लगा दी है। निजी रिफाइनरी युआन में भुगतान का निपटान कर सकते हैं। रूस के पास रुपये की अतिरिक्त सप्लाई है, जिसका इस्तेमाल करने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष में युआन की मांग तेजी से बढ़ी है और अर्थव्यवस्था इम्पोर्ट के लिए चीन पर अधिक निर्भर हो गई है। रूसी बिजनेसमैन अपना ज्यादातर व्यापार युआन में ही कर रहे हैं। इस वर्ष चीनी मुद्रा डॉलर की जगह रूस में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा भी बन गई है। यदि तेल की कीमतें अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा रूसी तेल पर लगाई गई 60 डॉलर प्रति बैरल की सीमा से ऊपर हैं, तो भारतीय रिफाइनरी ज्यादातर रूसी तेल इम्पोर्ट के लिए दिरहम-संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा- अमेरिकी डॉलर और थोड़ी मात्रा में रुपये का भुगतान करती हैं।

## 'महुआ ने...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

मोइत्रा संवद के सबसे मुखर वक्ताओं में से रही है और सत्तारूढ़ पार्टी तथा प्रधानमंत्री पर हमलों से उन्हें काफी प्रचार मिला। शपथ पत्र में कुछ ऐसे बिन्दु हैं जो इस मशहूर सांसद के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि भाजपा ने इन आरोपों को लपक लिया और इनके सहारे मोइत्रा की कार्रवाइयों की अवैधानिकता सिद्ध कराने में लगी है। मीडिया के कुछ वर्ग जोर-शोर से इसका प्रचार कर रहे हैं।

## 'चीन के ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

पैसेफिर क्षेत्र में चीन की सेना के एयर इन्टरसैप्ट्स रिकॉर्ड किए है इनमें से एक अमेरिका के विमान से 10 फीट दूर ही था।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908